<u>राज्य सभा</u>

अतारांकित प्रश्न संख्या 622

07 फरवरी, 2018 को उत्तर के लिए

देश में कच्चे इस्पात के उत्पादन में वृद्धि

622. श्री के. आर. अर्जुननः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष देश में कच्चे इस्पात के उत्पादन में लगभग 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह अब तक के सर्वाधिक उत्पादन के आंकड़े, 101.28 मिलियन टन तक पहुंच गया;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार घरेलू इस्पात क्षेत्र को बढ़ावा देने और इसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने हेतु विभिन्न उपाय कर रही है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने एक नई नीति को अनुमति दी है जिसका लक्ष्य है वर्ष 2030 तक 10 लाख करोड़ के अतिरिक्त निवेश के साथ 300 मिलियन टन की इस्पात-विनिर्माण-क्षमता प्राप्त करना; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

इस्पात राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय)

(क): जी हाँ। विगत वर्ष के दौरान भारत का क्रूड इस्पात उत्पादन 6.18 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 100 एमटी पार कर चुका है, जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:-

अवधि	क्रूड इस्पात उत्पादन (एमटी)	विगत वर्ष की समान अवधि की तुलना में % बदलाव*
जनवरी-दिसंबर 2017*	101.371	6.18
जनवरी-दिसंबर 2016	95.47	-
स्रोत: जेपीसी एमआईएस रिपोर्ट, दिसंबर 2017; * अनंतिम; एमटी= मिलियन टन		

(ख): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है तथा सरकार की भूमिका एक सुविधादाता के रूप में होती है। सरकार ने देशीय इस्पात क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए विविध उपचारी उपाय किए हैं जिनमें अन्य के साथ-साथ व्यापारिक उपाय, जैसे कि एंटी डंपिंग शुल्क लगाना, सेफगार्ड शुल्क लगाना और न्यूनतम आयात कीमतों को अस्थायी रूप से लागू करना शामिल है; गुणवत्ता नियंत्रण आदेश को सूचित किया है, जो सभी इस्पात उत्पादों और आयातों के संबंध में बीआईएस मानकों के उपयोग को अनिवार्य बनाता है; सरकारी खरीद में घरेलू निर्मित लोहा और इस्पात उत्पादों के उपयोग की नीति अधिसूचित की है, जो घरेलू मूल्यवर्द्धन को सुविधाजनक बनाती है; तथा घरेलू इस्पात क्षेत्र में दीर्घकालीन विकास को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 को अधिसूचित किया है।

(ग) और (घ): जी हाँ। राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 में क्रूड इस्पात क्षमता को वर्ष 2030-31 तक 300 एमटी बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 की मुख्य विशेषताएं हैं:-

- राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 वर्ष 2030 तक इस्पात निर्माण क्षमता को 300 एमटी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए आशान्वित है। इससे इस्पात क्षेत्र में वर्ष 2030-31 तक 10 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश होगा और इसमें 1.1 मिलियन अतिरिक्त कार्यबल को रोजगार प्राप्त होगा।
- यह नीति इस्पात की खपत को बढ़ाने का प्रयास करती है तथा इसके मुख्य आयाम अवसंरचना, ऑटोमोबाइल और आवास है।
- राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 वर्ष 2030-31 तक इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत को लगभग 61 किलोग्राम के स्तर से बढ़ाकर 160 किलोग्राम तक करने के लिए प्रयासरत है।
- नीति में यह निर्धारित किया गया है कि समग्र उत्पादकता को बढ़ाने और विद्युत की अत्यधिक खपत को कम करने के लिए इस्पात के छोटे उत्पादकों को कम विद्युत खपत वाली प्रौद्योगिकियाँ अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।

******